# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 168/2019

गोपाल राम पुत्र श्री नानू राम चौधरी, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी ग्राम कूणी, डाक चौसला, तहसील नावां, जिला नागौर. (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. राजस्व बोर्ड, अजमेर, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से.
3. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी), जयपुर, अपने सचिव, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर 302018 (राज.) के माध्यम से.

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री महावीर भांवरिया.

प्रतिवादी (गण) की ओर से : श्री एस.आर. पालीवाल.

## माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

## आदेश (मौखिक)

**19/02/2025**

1. यहाँ याचिकाकर्ता, अन्य बातों के अलावा, प्रतिवादीगण को यह निर्देश देने की माँग करता है कि वे उसके कंप्यूटर कोर्स प्रमाण पत्र को आरएस-सीआईटी कोर्स के समकक्ष मानें और उसे उन कम योग्यता वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की तिथि से पटवारी के रूप में नियुक्ति प्रदान करें, साथ ही सभी आनुषंगिक लाभ भी दिए जाएँ।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने अपने कंप्यूटर प्रमाण पत्र को आरएस-सीआईटी कोर्स के समकक्ष मान्यता देने का अनुरोध करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 से संपर्क किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को उसके प्रमाण पत्र की आरएस-सीआईटी कोर्स के साथ समकक्षता के बारे में जारी करने वाले प्राधिकारी से पुष्टि प्राप्त करने की सलाह दी. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण के लिए 25/11/2018 को महानिदेशालय पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया। 06/12/2018 को, महानिदेशालय ने स्पष्ट

किया कि डीओईएसीसी, जो एक केंद्र सरकार का निकाय है, की ओर से क्रिएटिव कंप्यूटर्स, ठाणे द्वारा संचालित कंप्यूटर कोर्स को आरएस-सीआईटी कोर्स के समकक्ष माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तब 12/12/2018 को प्रतिवादी संख्या 3 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पटवारी पद के लिए उसकी पात्रता हेतु उसके प्रमाण पत्र को मान्यता देने का अनुरोध किया। हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2.1. वह आगे तर्क देते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि एम-एस-सीआईटी सहित अन्य राज्यों के प्रमाण पत्रों को पटवारी पद के लिए स्वीकार किया जाएगा । इसलिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र को भी आरएस-सीआईटी कोर्स के समकक्ष माना जाना चाहिए। चूंकि अन्य राज्यों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह उचित है कि पटवारी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र को भी समकक्ष माना जाए।

3. प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया प्रासंगिक पक्ष पैरा संख्या 8 और 9 में है। उचित होने के कारण, इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "*8.* रिट याचिका के पैरा संख्या *8* और *9* की सामग्री के उत्तर में उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पटवारी के पद के लिए पात्रता मानदंड चयन और शैक्षणिक योग्यता पर विचार राजस्थान भू-राजस्व *(*भूमि अभिलेख*)* नियम, *1957* द्वारा शासित होता है और इस प्रकार एक उम्मीदवार की पात्रता का निर्धारण *1957* के नियमों के संदर्भ में और नियमों के अनुसार किया जाना है *।* आरएस-सीआईटी कंप्यूटर कोर्स की अवधि *90* दिन की होनी चाहिए जबकि याचिकाकर्ता ने *04.02.2008* से *26.04.2008* तक कंप्यूटर कोर्स किया है इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कोर्स *1957* के नियमों में दिए गए अनुसार आरएस-सीआईटी के समकक्ष नहीं है इस प्रकार उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सका *।*
>
> *9.* रिट याचिका के पैरा संख्या *10* की सामग्री पर उत्तर देने वाले प्रतिवादी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अभिलेख का मामला है लेकिन यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता ने रक्षा मंत्रालय से उस कंप्यूटर कोर्स के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था जो उसने किया था कि क्या वह आरएस-सीआईटी के कंप्यूटर कोर्स के समकक्ष है, लेकिन चूंकि आरएस-सीआईटी कोर्स की अवधि *90* दिन की है और याचिकाकर्ता ने *83* दिन का कोर्स किया था और इसलिए रक्षा मंत्रालय इस तथ्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कोर्स आरएस-सीआईटी के समकक्ष नहीं है*."*

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. सबसे पहले, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से सहमत नहीं हो सकता कि विज्ञापन में प्रमाण पत्र की कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है। प्रमाण पत्र की स्वीकार्यता विशेषज्ञों को देखनी है और उसी के आधार पर आरएस-सीआईटी के प्रमाण पत्र को एक मानक (बेंचमार्क) माना गया और उक्त मानक 90 दिनों के कोर्स की न्यूनतम अवधि पर आधारित है।यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता ने 04.02.2008 से 26.04.2008 तक शुरू होकर केवल 6 सप्ताह का कंप्यूटर कोर्स किया है और इसलिए उक्त कोर्स को विज्ञापन के अनुसार समकक्ष नहीं पाया गया। याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने से उन लोगों के साथ उल्टा भेदभाव होगा जो समान स्थिति में थे और जिन्हें अपात्र माना गया था और इस प्रकार वे विचाराधीन पद के लिए आवेदन नहीं कर सके।

6. केवल विज्ञापन के खंड 7(iii) के अनुसार पात्रता की शर्त को देखना है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:-

> "इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कंप्यूटर कोर्स मान्यता (डीओईएसीसी) इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संचालित 'ओ' लेवल या उन्नत लेवल प्रमाण पत्र।"

7. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि या तो उम्मीदवार के पास 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो डीओईएसीसी द्वारा विधिवत प्रायोजित हो, या वह आरएस-सीआईटी होना चाहिए। स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता के पास आरएस-सीआईटी प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उसके पास एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-1) है जो क्रिएटिव कंप्यूटर्स द्वारा जारी किया गया है, जो केवल यह कहता है कि उसने मूल कंप्यूटर अनुप्रयोग में एक कोर्स किया है। यह 'ओ' लेवल होने की योग्यता नहीं रखता है।

8. महानिदेशालय पुनर्वास के कार्यवाहक निदेशक प्रशिक्षण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3-चयन बोर्ड को संबोधित उनके पत्र दिनांक 06.12.2018 पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया जोर, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि याचिकाकर्ता द्वारा क्रिएटिव कंप्यूटर्स में किया गया मूल अनुप्रयोग कोर्स, जो डीओईएसीसी द्वारा प्रायोजित था, को राजस्थान राज्य कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के समकक्ष मान्यता दी जानी चाहिए, भी अमहत्वपूर्ण है जैसा कि ऊपर पहले ही देखा जा चुका है। पात्रता विज्ञापन के अनुसार होनी चाहिए और रक्षा सेवाओं के गैर-विशेषज्ञ अधिकारी की सिफारिश के आधार पर नहीं, जिन्होंने एक पूर्व सैनिक की मदद करने के उत्साह में,

प्रमाण पत्र के न्यूनतम स्तर की आवश्यकता को शिथिल करने का अनुरोध किया है, जिसे स्पष्ट रूप से 'ओ' स्तर या आरएस-सीआईटी के रूप में निर्धारित किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए मैं प्रतिवादीगण द्वारा दायर उत्तर में लिए गए बचाव से सहमत हूँ।

9. इस आधार पर, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. खारिज किया जाता है।

11. लंबित आवेदन (यदि कोई हो) निपटाए जाते हैं।

**(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति**

89-/जितेंद्र/सुमित

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं.

**अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।**

**एडवोकेट विष्णु जांगिड़**